

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 631]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 24 सितम्बर 2019 — आश्विन 2, शक 1941

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 24 सितम्बर 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-43/2019/1/एक. — राज्य शासन एतद्वारा माननीय मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्य मंत्री एवं उप मंत्री द्वारा दिये जाने वाले स्वेच्छानुदानों को विनियमित करने के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.-** (1) यह नियम मंत्रि-परिषद सदस्य स्वेच्छानुदान नियम, 2019 कहलायेंगे।
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- परिभाषाएं.-** इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) “राज्य शासन” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
(ख) “मंत्रि-परिषद सदस्य” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्य मंत्री एवं उप मंत्री;
(ग) “स्वेच्छानुदान” से अभिप्रेत है माननीय मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्य मंत्री एवं उप मंत्री द्वारा अपने विवेकाधीन निधि से दिया जाने वाला अनुदान;
(घ) “नियम” से अभिप्रेत है स्वेच्छानुदान नियम, 2019.
- स्वेच्छानुदान की स्वीकृति.-** (1) इन नियमों के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्य मंत्री एवं उप मंत्री के द्वारा किसी भी पात्र व्यक्ति को अथवा संस्था को अपने विवेकाधीन निधि से अनुदान दिया जा सकेगा।
(2) माननीय मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्य मंत्री एवं उप मंत्री को प्राप्त आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज, यदि कोई हो, के आधार पर स्वेच्छानुदान स्वीकृत किया जा सकेगा, किन्तु मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्य मंत्री एवं उप मंत्री आवेदन के बिना भी, अपने विवेकानुसार पात्र व्यक्ति/संस्था को अनुदान स्वीकृत कर सकेंगे।

(3) जहां आवश्यक होगा वहाँ मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्य मंत्री एवं उप मंत्री संबंधित जिले के कलेक्टर से प्रतिवेदन मंगवा सकेंगे।

4. **स्वेच्छानुदान स्वीकृति के उद्देश्य.**— मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्य मंत्री एवं उप मंत्री स्वविवेक से निम्न उद्देश्यों एवं प्रयोजनों के लिए साधारणतया छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर निवासरत व्यक्ति को छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर स्थित संस्था को अनुदान स्वीकृत कर सकेगा :—

(1) **व्यक्ति विशेष के मामले में:**— खेलकूद, शिक्षा, कला, विज्ञान, ईमानदारी एवं वीरतापूर्ण कार्य के लिए पुरस्कार स्वरूप अनुदान, चिकित्सा हेतु अनुदान, निराश्रित या दिव्यांग व्यक्ति को अनुदान, कन्या विवाह हेतु अनुदान, स्वरोजगार हेतु अनुदान, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को अनुदान, अनाथ (नाबालिग होने पर पालक के नाम पर) को अनुदान, बच्चों के शिक्षण हेतु (पालक/शिक्षण संस्था के नाम पर) अनुदान।

(2) **संस्था के मामले में:**— इसके तहत ऐसे सभी सार्वजनिक प्रयोजन शामिल होंगे, जो जनहित के स्वरूप के हों।

स्पष्टीकरण :— विशुद्धतम राजनैतिक तथा धार्मिक स्वरूप की संस्थाओं को कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा, किन्तु विशुद्धतम राजनैतिक/धार्मिक स्वरूप की संस्थाओं से भिन्न अन्य संस्थाओं को अनुदान दिया जा सकेगा। संस्था को पंजीकृत होना आवश्यक नहीं होगा।

5. कोई आवर्ती व्यय नहीं किया जा सकेगा।

6. **सहायता की राशि.**— मुख्यमंत्री के द्वारा किसी भी प्रकरण में उद्देश्य की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए स्वेच्छानुदान राशि स्वीकृत की जायेगी, जो किसी भी एक वर्ष में किसी एक व्यक्ति/संस्था को रुपये 2000/— से अन्यून एवं रुपये 5.00 लाख से अनधिक तथा उप मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्य मंत्री एवं उप मंत्री द्वारा रुपये 2000/— से अन्यून एवं रुपये 40,000/— से अनधिक स्वीकृत की जा सकेगी।

7. स्वेच्छानुदान की वार्षिक राशि की सीमा.—माननीय मुख्यमंत्री को 10.00 करोड़ (रूपये दस करोड़), माननीय उप मुख्यमंत्री/मंत्रियों को 1.50 करोड़ (रूपये एक करोड़ पचास लाख), माननीय राज्य मंत्री/उप मंत्री को रूपये 1.00 करोड़ (रूपये एक करोड़) होगी।
8. समस्त व्यय की लेखा परीक्षा की जाएगी।
9. आहरण की प्रक्रिया.— माननीय मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री द्वारा स्वीकृत अनुदानों की रकम के भुगतान के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :—

(क) जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री या अन्य माननीय मंत्रिगण कोई अनुदान देने का निर्णय करें वैसे ही मुख्य सचिव, महालेखाकार को आदेशों की एक प्रति भेजेगा, जिसके साथ मुख्य लेखा अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा हस्ताक्षरित एक सादी रसीद भी होगा। मुख्य सचिव द्वारा आदेशों की एक प्रति वित्त विभाग को भेजी जानी चाहिए, ताकि वह वार्षिक आवंटन के प्रगति की जांच कर सकें।

(ख) प्रत्येक ऐसे मामले को, जिसमें कोई अनुदान मंजूर किया गया हो, मुख्य लेखा अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा माननीय मुख्यमंत्री की जानकारी में लाया जाना चाहिए ताकि वे दिए गए प्रत्येक अनुदान के संबंध में माननीय मंत्रियों को अवगत करा सकें, जिससे कि भविष्य में किसी संस्था को अनुदान देने के संबंध में अपने विवेक का प्रयोग करते समय उन्हें यह बात मालूम रहे कि संस्था को किसी अन्य माननीय मंत्री से अनुदान पहले ही प्राप्त हो चुका है। यह बात, योग्य मामलों में, उसी संस्था को दूसरा अनुदान देने के संबंध में माननीय मंत्री को नहीं रोकेगी।

(ग) ये अनुदान कोषागार संहिता, जिल्द—एक के उप—नियम (एस.आर.) 424 में निर्धारित उपबंधों के अनुसार दिए जायेंगे।

(घ) विवेकाधीन अनुदान के प्रयोजनार्थ मुख्य लेखा अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, आहरण अधिकारी होगा।

(ड.) (1) माननीय मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री से प्रस्ताव प्राप्त होने पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किये जायेंगे, जिसकी प्रति मुख्य लेखा अधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर एवं प्रतिलिपि संबंधितों को भेजी जायेगी।

(2) स्वीकृति आदेश जारी होने के पश्चात मुख्य लेखा अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर से राशि का आहरण किया जायेगा, तथा स्वीकृत राशि संबंधित कलेक्टरों को उपलब्ध कराई जायेगी।

(3) संबंधित कलेक्टर स्वीकृत राशि के चेक संबंधित अनुदान ग्रहिता को वितरित कर प्राप्ति रसीद एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र/स्टाम्प रसीद आदि प्राप्त कर, मुख्य लेखा अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को भेजेंगे। मुख्य लेखा अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र/स्टाम्प रसीद आदि का संधारण आडिट हेतु किया जायेगा एवं अंतिम लेखा परीक्षा के लिए महालेखाकार को आदाता की रसीद अग्रेषित करेगा।

(च) अनुदान का भुगतान आवश्यकतानुसार या तो ड्राफ्ट द्वारा या मनिआर्डर द्वारा किया जा सकेगा और मनिआर्डर के मामलों में पोस्टल कमीशन सचिवालयीन आकस्मिकताओं में विकलित कर दिया जायेगा।

10. यदि कोई भी दिया जाने वाला अनुदान, स्वेच्छानुदान नियमों में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के अध्यधीन तथा निर्धारित राशि की सीमा के भीतर न हो तो उपयुक्त पाये जाने वाले प्रकरण में मुख्यमंत्री द्वारा नियमों को शिथिल कर, स्वीकृत किया जा सकेगा, बशर्ते स्वीकृत अनुदान बजट में प्रावधानित राशि के अन्तर्गत देय हो। स्वीकृति आदेश जारी किये जाने के पश्चात् ऐसे प्रकरणों में मंत्रि-परिषद का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

11. निर्वचन.— इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम माना जायेगा।

12. **निरसन.**— इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पहले प्रवृत्त समस्त मार्गदर्शी सिद्धांत, आदेश तथा निर्देश, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, सचिव.